साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 अंक 13 प्रति सोमवार इंदौर, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 पृष्ठ 8 मूल्य 2/- रुपए

मोदी की विदेश नीति सबसे कमजोर

वर्तमान में देश शत्रुओं से घिरा हुआ, चारों तरफ चीन ने सभी छोटे देशों को भारत के विरुद्ध खड़ा करा

भारत आज अपने पड़ोसी देशों के बीच बहुत कमजोर और अकेला पड़ गया है। एक-एक कर इसके सभी पड़ोसी देश चीन की गोद में बैठते जा रहे हैं। एक ही नज़र में दिखाई देता है कि चीन ने भारत की पूरे 360° में ऐसी घेरेबंदी कर दी है कि इसके सभी पड़ोसी देशों से सम्बंधों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है।

नेपाल और श्रीलंका पहले ही चीन की गोद में जा बैठे हैं। जिनमें चीन ने भारी निवेश किया है।

तमाम तरह की मदद करने के बाद भी अफगानिस्तान से हम पहले ही भगा दिये गये। ईरान ने चाबहार से भारत को निकाल बाहर कर दिया। उधर अरब देश भी भृकुटि ताने बैठे हैं।

भूटान अपनी विदेश नीति भारत द्वारा संरक्षित होना भुलाते हुए डोकलाम पर चीन से हमारे बगैर समझौता कर रहा है। भूटान और चीन के बीच 25वें दौर की सीमा वार्ता चल रही है, जो 2016 के आखिरी दौर के बाद से रुकी हुई है; बीजिंग थिम्पू के साथ पूर्ण राजनयिक सम्बंधों पर जोर दे रहा है।

बांग्लादेश में चीन कई विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है। चीन को अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआइ) परियोजना में गहराई से शामिल करने की चीन की दिलचस्पी के चलते दोनों देशों के सम्बंध पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं। जबकि भारत में NRC की जड़ बंगलादेशी शरणार्थियों का मामला स्थाई तनाव का आधार बना हुआ है, जो भारत में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा है।

मालदीव में चलाए गए 'इंडिया आउट' कैंपेन के बल पर चुन कर आई नई सरकार ने वहां तैनात भारतीय फौज को वापस जाने को

कह दिया है। इसके अलावा हफ्ता भर पहले बने नये राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत से पल्ला झाड़ते हुए चीन के साथ फ्री-ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी कर रहे हैं।

अब रहा पाकिस्तान तो, वह स्वघोषित राष्ट्रवादियों के नजरिए से स्थाई दुश्मन देश है ही।

अभी सिर्फ 15 साल पहले तक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस—SAARC) के देशों पर भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। और, वह भी एक दौर था जब भारत 120 सदस्य और 17 पर्यवेक्षक देशों वाले गुट-निरपेक्ष देशों का नेतृत्व करता था।

स्वघोषित विश्वगुरु मोदी की हवाबाजी के चक्कर में अपना सबकुछ खोते जा रहे भारतीय जनमानस के एक छोटे-से हिस्से को यह सब समझ नहीं आ रहा है। वह बुद्धिहर्ता प्रोपेगंडा-तंत्र के दुष्प्रचार का शिकार होकर जिसे डंका बजना कहता है, दरअसल वह इस देश की तबाही की वैश्विक घोषणा है।

जरा गौर कीजिए कि इससे पहले इतना कमजोर, इतना अकेला भारत कभी आपने सपने तक में नहीं देखा होगा।

जिसने खुद 35 साल तक भीख मांगते हुए गुजारा किया हो, वह नालायक क्या जाने कि घर-गृहस्थी या समाज का संचालन कैसे किया जाता है और रचनात्मकता किस चिड़िया का नाम है। वह सबकुछ तबाह करके बड़ी आसानी से लोगों के हाथ में कटोरा ही थमाएगा। यही सनातन सत्य है।

मोदी बने देश को सबसे ज्यादा कर्ज में डुबाने वाले पहले प्रधानमंत्री

नरेन्द्र मोदी अब तक के सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। ये कांग्रेसियों या वामपंथियों के IT सेल की रिपोर्ट नहीं, बल्कि विश्व बैंक की रिपोर्ट है जो World Bank की Official Website पर उपलब्ध है....

सोशल मीडिया पर यह मिथ्या ख़बर पिछले 4 महीनों से फैलाई जा रही है कि हमारी सरकार बिना विश्व बैंक से लोन लिए ऐतिहासिक विकास कर रही है...

ये भ्रम से बाहर आकर यह जानने का वक़्त है, कि नरेन्द्र मोदी अब तक के सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। ये कांग्रेसियों या वामपंथियों के ध्क सेल का रिपोर्ट नहीं, बल्कि विश्व बैंक का रिपोर्ट है जो World Bank की Official Website पर उपलब्ध है।

बीजेपी आईटी सेल के द्वारा फैलाये गए भ्रामक ख़बरों के आधार पर प्रधानमंत्री समर्थकों द्वारा बुलंद आवाज में सामान्य लोगों के

बीच इस भ्रम को और भी विस्तार से फैलाया जाता रहा है कि प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ने शासन की बागडोर संभालने के बाद से वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 तक विश्व बैंक से एक रुपये का भी कर्ज नहीं लिया है।

सोशल मीडिया पर यह मिथ्या ख़बर पिछले 4 महीनों से फैलाई जा रही है कि हमारी सरकार बिना विश्व बैंक से लोन लिए ऐतिहासिक विकास कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि भारत जैसे अर्थव्यस्था का पूर्णतः स्वाबलंबी हो पाना असंभव है, खासकर ऐसी स्थिति में जब डालर के मुकाबले रुपये के मूल्य निरंतर गिरते रहे हैं।

बाजार में प्रति बैरल तेल के दाम की तुलना में भारत में तेल के मूल्य में निरंतर वृद्धि हो रही है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय निर्यात इसके आयात के मुकाबले कम ही रही है। यह भी सत्य है कि भारत जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था है,

(शेष पेज 3 पर)

आपराधिक मानसिकता के अमित शाह देश को अपनी बपौती न समझें

देश संविधान से चलेगा धमकियों से नहीं...

चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी के नेताओं, अधिकारियों को फर्जीवाड़ा करने के लिए बेबस कर रहा है

मध्य प्रदेश में वर्तमान में देश के केंद्र सरकार के गृहमंत्री अमित शाह ने सॉरी मर्यादाओं को लांघते हुए जिस प्रकार से आतंकियों की भाषा का उपयोग कर अपनी तड़ीपार होने के पुराने इतिहास को दोहरा कर सभी कर्मचारियों अधिकारियों को आने वाली 17 नवंबर के चुनाव में कमल के निशान का ध्यान न रखने पर धमका कर कहा कि शिवराज जी ऐसे कर्मचारियों को एसएमएस भेज दो धमका दो। क्या सिद्ध करती है। कि देश में कानून और चुनाव आयोग है ही नहीं। उच्च पद पर बैठे होने के बावजूद भी स्वयं ही अपनी गुंडागर्दी का परीक्षा देते हुए न केवल अपने पार्टी के विपक्ष के नेताओं को धमकाओ कर्मचारियों अधिकारियों को खुले में कमल के निशान का ध्यान न रखने, अर्थात सत्ताधीशों को चुनाव जिताने के लिए जालसाजी व चुनाव में मतदान के समय फर्जीवाड़ा करने की खुली छूट दे रहा है। उन्हें जिताने के लिए फर्जी वाड़ा ना करने न मानने पर उनको परेशान करने, नौकरी से हटाने की खुली धमकी दे रहा है। तड़ीपार अमित शाह इवीएम के फर्जीवाड़े से सत्यता हथिया तो ली। पर अपना चाल चरित्र चेहरा बदल नहीं पाये। देश के गृहमंत्री सत्ता अपने बाप की जागीर नहीं। जो मंचों पर खड़े होकर सीधे गुंडो की भाषा बोलकर न केवल अपने ही पार्टी के नेताओं को धमकाने से लेकर विपक्ष के नेताओं के साथ सरकार में बैठे सभी आईएएस आईपीएस आईएफएस व अन्य अधिकारियों के साथ सरकार के 150 से ज्यादा विभागों मंडलों कंपनियों के अधिकारियों कर्मचारियों को धमका रहे हो। (शेष पेज 3 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

हिंदुओं के त्योहारों से देश के अर्थव्यवस्था हरी भरी

भारत में सनातन धर्म की लाखों साल पुरानी धार्मिक परंपराएं विश्व के सभी देशों से हमारे देश को कई महीनो में न केवल अलग बनाती है वर्णन सबसे महत्वपूर्ण हमारे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जनता को प्रसन्न रखना उनकी आय की व्यवस्था करने के साथ देश के बाजारों को लगातार चलाएं मान रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है यही कारण है कि साल भर के 12 महीना में हर महीने में छोटे-मोटे त्यौहार होने के साथ हर मौसम बदलने के साथ चार महीने में एक बड़े त्यौहार होने के कारण देश के बाजारों में लगातार ग्राहक बना रहता है और अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार में अगर ग्राहक बना हुआ है तो मंदी की संभावना नहीं रहती। हमारे देश के त्यौहार न केवल हमारे देश के करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं वरन चीन जापान अमेरिका कोरिया ताइवान जैसे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं वर्तमान हालात तो यह है की हमारे त्योहार चीन की आधी अर्थव्यवस्था का आधार बन चुके हैं और यही कारण है कि मोदी के रहते हुए देश के लगभग 40 लाख से ज्यादा उद्योग बंद हो गएतो दूसरी तरफ चीन के खिलौने मूर्तियां और त्योहारो में उपयोग किए जाने वाली वस्तुओं यथा होली के रंग पिचकारी तो दिवाली पर बिजली की झालर पटाखे से लेकर इलेक्ट्रॉनिक अधिका लगभग 200000 करोड़ का बाजार चीन उपयोग करके मोटी कमाई करता हैजो हमारे सनातन धर्म के त्योहारों के दम पर है। इसके विपरीत जो भारत की अर्थव्यवस्था में हमारे सनातन धर्म के त्योहारों का महत्वपूर्ण भूमिका करोड़ों लोगों को रोजगार देती है, स्वयं मोदी ने 9 साल में उसे व्यवस्था को चौपट करने में आते ही साथ पहलेसफाई के नाम लगभग 5 करोड़ लोगों को जो सड़कों पर छोटी दुकानों पर ठेलो, पदमार्गों पर सब्जी भाजी फल फ्रूट रंगोली कपड़े व और घरेलूसामान बेचने से लेकर त्योहारों की सामग्री भेजा करते थे उन सबको खत्म कर दिया बाद में कैशलेस नोटबंदी जीएसटी और कोरोना की तालाबंदी में लगभग 25 करोड लोगों को बेरोजगार कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शॉपिंग मॉल वॉलमार्ट अडानी अंबानी टाटा बिरला की फैक्ट्री को चलाने के साथ चीन की अर्थव्यवस्था को उठाने में मुक्त हाथ से 25 करोड लोगों को रोजगार बना 50 लाख से ज्यादा उद्योग में खत्म कर सहयोग कर रहा है हमारे सनातन के त्यौहार विदेश के अर्थव्यवस्था चला रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं इसको भी सनातनियों के संरक्षण होने का पाखंड करने वाली आरएसएस और भाजपा को समझना चाहिए।

छोटे व्यापार और उद्योगों को खत्म करने का षडयंत्र

छोटे व्यापारियों का पॉलीथिन घातक, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का फायदेमंद

सरकार ने अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों अमेजॉन वॉलमार्ट भारत की आईटीसी युनिलीवर कैडबरीज कोको कोला पानी की बोतल पैकिंग जैसी कंपनियों व देश के पूंजी पतियों अंबानी अडानी टाटा बिरला मित्तल आदि के इशारे पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 जिसकी शुरुआत रिलायंस रिटेल में 2001 में अटल के प्रधानमंत्री रहते हुए कर दी थी। जिसका उद्देश्य था देश के सारे छोटे उद्योगों बाजारों मंडियों खाद्य विक्रेताओं दुकानों को खत्म कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंगुल में सारे देश की जनता को उलझा कर हर महीने हजारों करोड़ की कमाई की जाए।

यह कानून खासतौर से अंबानी की रिलायंस पैट्रोलियम से निकलने वाले सह उत्पाद पॉलीथिन का बड़ा बाजार हाथ में लेकर मोटी कमाई करने का था।

इस कानून के अंतर्गत सारी खाद्य पदार्थों को पैकेजिंग करने का प्रावधान है। और सभी खाद्य पदार्थों में घातक जहरीले कीटनाशक प्रिजर्वेटिव्स वक्त स्वाद बढ़ाने वाले रसायन मिलाकर पैकेजिंग कर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शॉपिंग मॉल से बेंचना। वर्तमान में सारी पैकेजिंग रिलायंस के प्लास्टिक मटेरियल से ही होती है।

भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का खाद्य नियंत्रक विभाग भी मानता है की 96.4% पैकेजिंग मैटेरियल लिवर किडनी हर्ट लंग्स जॉइंट्स आदि की विभिन्न प्रकार की फेल होने कैंसर होने आदि की बीमारियां बांटता है। परंतु डब्ल्यूएचओ के इशारे पर लगाए गए इस कानून को बनाने में 300 लाख करोड़ रु कानून निर्माताओं को मिले।

इसमें हर सांसद को 1000 करोड़ रू कानून पर हस्ताक्षर करने का मिला। अकेले वॉलमार्ट ने इस कानून के लिए 33.5 लाख करोड़ रु सन 2001 2 में ही खर्च कर दिए थे। इसलिए यह कानून विपक्ष के दबाव में कांगेस के कार्यकाल में बनाया गया। उनके रहते हुए, लागू नहीं होने दिया।

उस कानून को पूरा करने के लिए मोदी ने आते ही सफाई के नाम देश के बाजारों से2कर ठेले, फुटपाथ वालों को साफ कर दिया जिससे शॉपिंग मॉल का बाजार चमक उठा। उसके बाद 2015 में कैशलेस, 2016 में नोटबंदी, 2017 जीएसटी और 2020 ताला बंदी कर देश में 40 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना अमेजॉन वॉलमार्ट के साथ अडानी अंबानी टाटा बिरला को दुनिया का दूसरे तीसरे चौथे नंबर का अमीर बना दिया। तो अगर प्लास्टिक बंद करना है। तो सबसे पहले किसान आंदोलन की तरह जनता को बाहर निकल कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 को हटवाना चाहिए।

छोटे दुकानदार पॉलीथिन उपयोग करें तो बीमारी और बड़े उपयोग करें तो स्वास्थ्यवर्धक। छोटा दुकानदार दो ढाई सौ ग्राम पॉलिथीन उपयोग करता होगा। पर कचरा गाड़ियों में निगाह घुमा लीजिए 90% टनों से कचरा प्लास्टिक का बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पैकेजिंग मैटेरियल का होता है।

इसको समझें और बताएं
यह कौन सा न्याय है।

आप बेहतर आंकलन और कर सकते हैं।

मशहूर शायरों के मशहूर शे'र...

खींचो न कमानों को न तलवार निकालो
जब तोप मुक़ाबिल हो तो अखबा़र निकालो

अकबर इलाहाबादी

हमारे शहर के लोगों का अब अहवाल इतना है
कभी अखबा़र पढ़ लेना कभी अखबा़र हो जाना

अदा जाफ़री

टैग जो दिल को है खबर कहीं मिलती नहीं खबर
हर सुब्ह इक अज़ाब है अखबा़र देखना

उबैदुल्लाह अलीम

टैग इस वक़्त वहाँ कौन धुआँ देखने जाए
अखबा़र में पढ़ लेंगे कहाँ आग लगी थी

अनवर मसूद

ज़रा सी चाय गिरी और दाग़ दाग़ वरक़
ये ज़िंदगी है कि अखबा़र का तराशा है

आमिर सुहैल

दस बजे रात को सो जाते हैं खबरें सुन कर
आँख खुलती है तो अखबा़र तलब करते हैं

शहज़ाद अहमद

मुझ को अखबा़र सी लगती हैं तुम्हारी बातें
हर नए रोज़ नया फ़ित्ना बयाँ करती हैं

बशीर महताब

सुर्खियाँ खून में डूबी हैं सब अखबा़रों की
आज के दिन कोई अखबा़र न देखा जाए

मख़मूर सईदी

रात के लम्हात खूनी दास्ताँ लिखते रहे
सुब्ह के अखबा़र में हालात बेहतर हो गए

नुसरत ग्वालियारी

कौन पढ़ता है यहाँ खोल के अब दिल की किताब
अब तो चेहरे को ही अखबा़र किया जाना है

राजेश रेड्डी

गुमनाम एक लाश कफ़न को तरस गई
काग़ज़ तमाम शहर के अखबा़र बन गए

इशरत धौलपुर

ऐसे मर जाएँ कोई नक़्श न छोड़ें अपना
याद दिल में न हो अखबा़र में तस्वीर न हो

ख़लील मामून

बम फटे लोग मरे खून बहा शहर लुटे
और क्या लिक्खा है अखबा़र में आगे पढ़िए

ज़हीर ग़ाज़ीपुरी

कोई नहीं जो पता दे दिलों की हालत का
कि सारे शहर के अखबा़र हैं खबर के बग़ैर

सलीम अहमद

कोई कॉलम नहीं है हादसों पर
बचा कर आज का अखबा़र रखना

अब्दुस्समद 'तपिश'

सुर्खियां अखबा़र की गलियों में गुल करती रहीं
लोग अपने बंद कमरों में पड़े सोते रहे
वो खुश़-नसीब थे जिन्हें अपनी खबर न थी
याँ जब भी आँख खोलिए अखबा़र देखिए

काले धन के खिलाफ लड़ाई में भारत को बड़ी सफलता, स्विस बैंक ने जारी की खातों और अकाउंट बैलेंस की नई जानकारी

काले धन के खिलाफ लड़ाई में भारत को बड़ी सफलता मिली है। स्विस बैंक में काला धन रखने वालों की अब खैर नहीं। स्विस बैंक ने भारत सरकार से भारतीय खाताधारकों का डेटा साझा किया है। स्विट्जरलैंड ने 104 देशों के साथ करीब 36 लाख वित्तीय खातों का विवरण साझा किया है। इसके तहत किन भारतीयों ने अपना पैसा स्विस बैंक में रखा है और कहां-कहां से ये रकम आई है, इसका ब्यौरा स्विस बैंक ने साझा किया। काला धन रखने वालों के खिलाफ भारत सरकार अब कड़ी कार्रवाई करेगी।

कॉर्पोरेट्स और ट्रस्टों सहित व्यक्तियों के नाम

स्विट्जरलैंड और भारत के बीच सूचनाओं का यह पांचवां वार्षिक आदान-प्रदान है। अधिकारियों ने कहा कि भारतीय अधिकारियों के साथ साझा किए गए नए विवरण सैकड़ों वित्तीय खातों से संबंधित हैं। इनमें कुछ व्यक्तियों, कॉर्पोरेट्स और ट्रस्टों से जुड़े कई खातों के कई मामले भी शामिल हैं।

खातों और अकाउंट बैलेंस की नई जानकारी

स्विस बैंक द्वारा विवरण साझा किए गए हैं उनमें पहचान, खाता और वित्तीय जानकारी शामिल है। इसमें नाम, पता, निवास का देश और कर पहचान संख्या, साथ ही रिपोर्टिंग वित्तीय संस्थान, खाता शेष और पूंजीगत आय से संबंधित जानकारी शामिल है।

रकम का डिटेल्ड खुलासा नहीं हुआ

अधिकारियों ने सूचना के आदान-प्रदान की गोपनीयता शर्त और आगे की जांच पर इसके प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए जानकारी और अन्य विवरण जारी किया हैं। इनमें राशि का खुलासा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस ब्योरे का इस्तेमाल टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और आंतकवाद के फंडिंग सहित अन्य अवैध और गलत कार्यों की जांच के लिए किया जाएगा।

104 देशों के 36 लाख वित्तीय खातों का जानकारी

स्विस राजधानी बर्न से एक बयान में, संघीय कर प्रशासन (एफटीए) ने सोमवार को कहा कि उसने सूचना के स्वचालित आदान-प्रदान (एईओआई) पर वैश्विक मानक के ढांचे के भीतर 104 देशों के साथ वित्तीय खातों पर जानकारी का आदान-प्रदान किया है। इस वर्ष, कजाकिस्तान, मालदीव और ओमान को 101 देशों की पिछली सूची में जोड़ा गया था। वित्तीय खातों की संख्या में लगभग दो लाख की वृद्धि हुई।

मोदी बने देश को सबसे ज्यादा कर्ज में डुबाने वाले पहले प्रधानमंत्री

पेज 1 का शेष

और स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सामाजिक संरचना, रक्षा, वैज्ञानिक प्रगति, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में जिन किन्ही परेशानियों से जूझ रहा उसमे पूंजी की कमी सर्वाधिक ध्यान देने योग्य है।

ऐसे में विश्व बैंक, IBRD, IDA, एसियन डेवलपमेंट बैंक सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों पर इसका निर्भर होना कोई आश्चर्य पैदा नहीं करता। चाहे सरकार या तंत्र किसी के भी हाथ में हो मगर इसके निरूपण, संचालन, रखरखाव व राजकोषीय कमी को पूरा करने के लिए ऐसे संस्थानों पर निर्भरता बेहद स्वाभाविक हो जाता है।

हास्यास्पद ये है कि आम जनता को जागरूक बनाने की बजाय सत्ताधारी दल के समर्थकों द्वारा बढ़ चढ़ कर यह अवांछित व झूठी ख़बरों को व्हाट्सएप, ट्वीटर व फेसबुक यूनिवर्सिटी पर धड़ल्ले से परोसा जा रहा है, ताकि आम जनता को लुभा सके। सत्ता की भूख ने नैतिकता को इतना बेबस कर दिया कि राजनेता से लेकर सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता इन्ही ख़बरों के सहारे वोट बटोरने की जुगत में लगे हैं।

मीडिया में बीजेपी समर्थकों से लेकर टेलीविजन स्क्रीन पर बैठे प्रवक्ताओं द्वारा लगातार हर विफलताओं के लिए कांग्रेस को कोसे जाने क्रम से आप भी अवगत हैं। एक भी सवाल जो सत्ताधारी दल के योजनाओं व कार्यों को लेकर इनके समक्ष खड़े किए जाते हैं उसका जवाब कांग्रेस के नाम का सहारा लिए बगैर संभव नही हो पाता या फिर सवाल की दिशा बदल दिए जाते हैं।

आए दिनों यत्र-तत्र व्हाट्सएप व फेसबुक जैसे प्लेटफोर्म पर यह ख़बरें खुमते हुए पायी जा रही है कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने विश्व बैंक से कर्जा लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था को दवाब में ला खडा किया है। यही नहीं साथ में यह भी कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने विश्व बैंक से कोई कर्ज नहीं लिया है। लेकिन जब इसकी पड़ताल की, तो पता चला कि इस अफवाह के पीछे का सच कुछ और ही है।

बैंक की वेबसाइट पर साफ तौर पर लिखा गया है कि भारत और विश्व बैंक के बीच इसी साल 2 फरवरी 2018 को एक करार हुआ है। इसके तहत विश्व बैंक ने भारत को वाराणसी से हल्दिया के बीच 1360 किमी का जलमार्ग बनाने के लिए 375 मिलियन डॉलर का कर्ज दिया है।

इस करार पर भारत की ओर से इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन प्रवीर पांडेय, भारत सरकार वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी समीर कुमार खरे, और भारत में विश्व बैंक के डायरेक्टर जुनैद अहमद ने हस्ताक्षर किए हैं।

गौरतलब यह है कि साल 2013 में भारत पर कूल विदेशी कर्ज का भार 409.4 अरब डॉलर (GDP का 11.1%) था जो 2014 में बढ़ कर 446.2 अरब डॉलर (GDP का 10.4%) तथा 2015 में 474.7 अरब डॉलर (GDP का 8.8%) हो गई और आगे यही भार प्रधानमंत्री मोदी की अगुआई में मार्च 2018 में 529 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया जिससे भारत का कूल विदेशी कर्ज में 12.4% की वृद्दि दर्ज की गई।

यह अब तक की सर्वाधिक सालाना वृद्धि है। यही नहीं यह भार इतनी अधिक हो गई कि GDP का 20.9% के बराबर पहुच गयी है। ऐसे में इस साल GDP में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि के जो आकड़े देश के सामने प्रस्तुत करके भ्रम फैलाए गए हैं यह भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का कितना विकृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। हमें यह समझने की जरुरत है सरकार GDP के आंकिक आंकड़े की आड़ में अपनी तमाम आर्थिक विफलताओं को ढकने की कोशिश कर रही।

उपलब्ध आंकड़े के आधार पर यह बात सामने आती है कि स्किल इंडिया, स्वच्छ भारत, गंगा की सफाई, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) शिक्षा, ऊर्जा क्षेत्र आदि के विकास के नाम पर अकेले प्रधानमंत्री मोदी ने तक़रीबन 78 अरब डॉलर का कर्ज अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से 2014 से 2018 के बीच लिया है। वर्ल्ड बैक के ही रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ल्ड बैंक एवं IBRD जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था से विश्व में सर्वाधिक लोन लेने वाला देश के रूप में अपनी पहचान रखता है।

ट्वीटर पर जून 2018 को sagarika4india द्वारा संचालित ट्वीटर अकाउंट द्वारा जो गलत सुचना शेयर किया गया था कि भारत के 70 सालों के इतिहास में केवल 3 साल ऐसे हैं जब भारत ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज नहीं लिया है 2015, 2016, 2017. इस पर हजारों लाइक्स और रिट्विट हुए जिसमें प्रधानमंत्री को हीरो बताया गया।

यही नही 2 जून को यह फेसबुक के राजनीति नामक पेज पर पोस्ट किया गया, जिसे 25,000 से ज्यादा लोगों ने शेयर किया। और फिर वहां से बीजेपी IT सेल द्वारा सक्रियता से इस झूठी खबर को आम जनता तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुचाया जाने लगा। बाद में Zee News Fan Group द्वारा भी यह ख़बरें खूब फैलाई गई। इस खबर की सत्यता को जांचे परखे बगैर आम जनता के बीच ये धारणा बनने लगी की मोदी ने सच में बीते 3 वर्षो में वर्ल्ड बैंक से एक भी पैसा कर्ज स्वरूप नहीं लिया।

मगर सत्य कितना भयावह है कि इस दौरान ही सरकार ने 96.56 अरब डॉलर (6952.32 अरब) का विशाल कर्ज लिया। यह बेहद आश्चर्य पैदा करता है कि हम शिक्षित समाज का हिस्सा होने के बावजूद भी बर्बाद को आबाद पढने लगे हैं।

2018 में लिए गए लोन के अलावा मोदी सरकार ने विश्व बैंक से जिन प्रमुख मुद्दों को परोस कर लोन लिया है उनका विवरण निम्नवत हैं :

लोन लेने की तिथि लोन लेने के उद्देश्य लोन का आकार

23 जनवरी 2018 उत्तराखंड में जल आपूर्ति 120 मिलियन डॉलर (8 अरब)

31 जनवरी 2018 तमिलनाडु के गांवों के हालत सुधार 100 मिलियन डॉलर (6.5 अरब रु)

24 अप्रैल 2018 म.प्र. के गांवों की सड़कें दुरुस्त करना 210 मिलियन डॉलर (करीब 14 अरब रु)

अप्रैल 2018 दवाई बनाने व गुणवत्ता में सुधार हेतु 125 मिलियन डॉलर (8 अरब 36 करोड़ रु)

8 मई 2018 राष्ट्रीय कुपोषण मिशन के लिए 200 मिलियन डॉलर (13.5 अरब रु)

29 मई 2018 राजस्थान के लिए 21.7 मिलियन डॉलर (1.5 अरब रु)

स्रोत : वर्ल्ड बैंक विभिन्न दस्तावेज, फाइनेंसियल 365

इसके अतिरिक्त अगर पिछले साल की बात करें तो उनमें कुछ चुनिंदा लोन में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में टूरिजम को विकसित करने के लिए 40 मिलियन डॉलर (2 अरब 67 करोड़ रुपये) का कर्ज, 21 नवंबर 2017 को सोलर पार्क प्रोजेक्ट के लिए 100 मिलियन डॉलर (6.5 अरब रुपये) का कर्ज, 31 अक्टूबर 2017 को असम में ग्रामीण परिवहन के लिए 200 मिलियन डॉलर (13.5 अरब रुपये) का कर्ज, 30 जून 2017 को नेशनल बायोफार्मा मिशन के लिए 125 मिलियन डॉलर (8 अरब 36 करोड़ रुपये) का कर्ज आदि सम्मिलित हैं, जो बीजेपी IT सेल व समर्थकों सहित आम जनता की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है।

यही नहीं, गंगा नदी जिसकी सफाई के लिए भारत अब तक विश्व बैंक से हजारों करोड़ रुपये का लोन ले चुका है। विश्व बैंक से कर्ज लेना सरकार की विफलता या कमजोरी नही कहा जा सकता मगर, झूठी ख़बरों को प्रचारित प्रसारित कर वास्तविक स्थिति से लोगों का ध्यान हटाने का यह प्रयास सरकार की तमाम विफलताओं की तरफ इशारा करती है इसमें कोई संशय नहीं।

हालांकि मात्र 3 वर्षो में अगर इतनी बड़ी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लों लिए गए तो इसका हिसाब कहाँ, और काम कितना हुआ है ये आप तय कीजिये। और अगर काम नही हो सके हैं तो आखिर ये लोन के पैसे गए कहाँ? याद रखिये इसे अंततः भारत को ही चुकाने हैं।

देश संविधान से चलेगा धमकियों से नहीं...

शाह बोले- जो भी अधिकारी कमल का ध्यान नहीं रखे, उसे छोड़ना नहीं

पेज 1 का शेष

भूतपूर्व तड़ीपार जिला बदर वर्तमान केन्द्र के गृहमंत्री अमित शाह ने जो अपराधियों की भाषा उपयोग की गई है। कि जो कमल के निशान का ध्यान नहीं रखेगा अधिकारी उसको देख लेने की धमकी, यह धमकी अभी तक तो विपक्ष के कहीं बड़े-बड़े नेताओं को देते थे इडी से छापे पड़वा के दिन नहीं माना तो सीबीआई से भी छापे पाड़वाए गए विपक्ष के नेताओं को जेल भिजवाया उनकी सांसद में से सदस्यता छीन ली यह सब सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाह जिला बगैर तड़ीपार भाषा का समावेश नजर आ रहा था अब तो हद हो गई की बड़े-बड़े आईपीएस एडीजीपी सबके सामने सीधा कहा गया है की जो कमल का ध्यान नहीं रखेंगे उनका इलाज कर दिया जाएगा यह क्या स्थिति पर देश पहुंच गया है कि इन तड़ीपरों से आईपीएस आईएएस जीपी अधिकारी भी कुछ मुंह नहीं खोल पाए एक समय इंदौर में डॉन वाला बैग ने एक पुलिस कर्मचारियों के ऊपर आक्रमण किया था तब इंदौर के दबंग आईजी सुरजीत सिंह दशमाना जी ने उसे नेस्तनाबूद कर दिया था वह बालाबेग का नाम लेवा भी नहीं बचा उनके नाम से इंदौर में दादा गिरी करने वालों को समाप्त कर दिया था क्या आज की तारीख में पूरे प्रदेश में इतना खुद्दार अधिकारी स्वाभिमानी कोई भी नहीं बचा जो कि इस बयान के बाद गृहमंत्री को सलाखों के पीछे ला सकता शायद अब इस देश में कोई भी पढ़ा लिखा अधिकारी इन तड़ीपार जिला बदर के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। इसे कहते हैं गुंडाराज आईपीएस आईएएस अधिकारी सबको धमकी देकर जा रहा है अगर इस प्रदेश में एक भी बहादुर मर्द होता आईपीएस अधिकारी डीजीपी मर्द होता तो इसे भोपाल में ही अरेस्ट कर लेता धमकी देने के आरोप में अपनी ही पार्टी के बागी उम्मीदवारों को भी इडी की धमकी दी आईएएस अधिकारियों को भी धमकी दी आईपीएस एडीजीपी कोई कुछ नहीं कर सका विपक्ष को भी धमकी इस सारी धमकियों के अंदर गृहमंत्री का भूतकाल नजर आ रहा है जिला बदर तड़ीपार व्यक्ति को हम किसी भी सीट पर बिठाएंगे उससे सीट की ईज्जत खराब हो जाएगी।

साप्ताहिक समय माया

असली बुलफाइटिंग

मध्य प्रदेश का मालवा-निमाड़ अंचल विधान सभा सीटों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा इलाका है. यहां कुल 66 सीटें हैं. उज्जैन और इंदौर जैसे इलाके इसी अंचल में आते हैं. यहां के मतदाताओं का स्वभाव अपने तौर का निराला है. लेकिन माना जाता है कि प्रदेश में सरकार उसी दल की बन पाती है, जिसे इस अंचल के मतदाताओं का विश्वास और वोट मिलते हैं. विंध्य और सतपुड़ा से घिरे निमाड़ को नर्मदा का सींचती है तो पठारी इलाके मालवा को चंबल और माही का पानी भी मिलता है. इस तरह से यहां संपन्न खेतिहर किसान हैं तो आदिवासियों की संख्या भी पर्याप्त है. लिहाजा सभी राजनीतिक दलों की मजबूरी है कि वे यहां किसानों-आदिवासियों की बात करें. मालवा में ही उज्जैन और इंदौर भी आता है. उज्जैन ही वो क्षेत्र है जो इतिहास में अवंतिका नगरी के नाम से दर्ज है. यहीं विक्रमादित्य का शासन था और यहीं संदीपनी का आश्रम है.

2018 चुनाव के नतीजे

ये तो मध्य प्रदेश के इस महत्वपूर्ण अंचल की पहचान हुई और यहां के मतदाता भी इन्हीं पहचानों के मुताबिक ही व्यवहार करते हैं. इस लिहाज से भी ये 66 सीटें सभी राजनीतिक दलों के लिए काफी कठिन मानी जाती है. अगर पिछले चुनाव के परिणाम देखे जाएं तो 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां की 66 सीटों में कांग्रेस को 35, बीजेपी को 28, और अन्य को एक तीन सीटें हासिल हुई थी. कमलनाथ सरकार गिरने के बाद 2020 में इस क्षेत्र की कुल 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे. उसमें छह सीटें बीजेपी को मिली थी और कांग्रेस को एक ही सीट से संतोष करना पड़ा. इस उपचुनाव के बाद कांग्रेस को एक सीट का नुकसान हुआ और बीजेपी को एक सीट पर बढ़त मिली.

किसान आंदोलन

2018 के चुनाव में इस क्षेत्र में जब कांग्रेस ने बढ़त बनानी शुरू की तभी कांग्रेस नेताओं के हौसले भी बढ़े. क्योंकि आम तौर पर इस इलाके के मतदाताओं पर बीजेपी का असर ठीक ठाक रहा. हालांकि बीजेपी का तिलस्म टूटने की बड़ी वजह भी इसी इलाके से पैदा हुई थी. चुनाव से पहले किसानों ने मंदसौर में आंदोलन किया और पुलिस ने फायरिंग की. यहां 5 किसानों की मृत्यु हुई और शिवराज सरकार की स्थिति बिगड़ने लगी. कांग्रेस आला-कमान ने भी इस घटना को मुद्दा बनाया किसानों से तमाम वायदे किए. बहुत से जानकार दावा करते हैं 2018 में एमपी में कांग्रेस को कुर्सी मिलने के पीछे तमाम कारणों की चर्चा की जाएगी तो किसान आंदोलन और किसानों पर गोली चलाए जाने को प्रमुखता से गिनते हैं.

...और कमलनाथ सरकार गिर गई

यहां इसका जिक्र करना भी जरूरी लगता है कि किसानों के मसले को ही मुद्दा बना कर उस वक्त कांग्रेस नेता के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री कमलनाथ का विरोध शुरु किया था. इसका नतीजा ये हुआ कि कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री की मिल गई.

आदिवासियों का मुद्दा

इस क्षेत्र में आदिवासियों के सीधे असर वाली 22 सीटें है. बीजेपी को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुकी है. 2003 में पहली बार बीजेपी को यहां उन सीटों पर भी आदिवासियों के बीच पकड़ बनाने पर थोक के भाव यहां सफलता मिली. उस चुनाव में बीजेपी ने 51 सीटे जीतने में सफलता पाई. इनमें कई ऐसी सीटें भी थी, जिन पर पारंपरिक रूप से कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था.

इसे ही समझते हुए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासियों के हितों की बात की है. आदिवासियों को रिझाने वाली कई परियोजनाएं भी शुरु की है. वैसे कांग्रेस भी पीछे नहीं रही. राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपनी पदयात्रा की शुरुआत इसी इलाके से की. कांग्रेस ने इसी क्षेत्र के बुहरानपुर से जीतने वाली जमुना देवी को दो बार उपमुख्यमंत्री की कुर्सी भी सौंपी. इस क्षेत्र से दिग्गज कांग्रेस नेताओं में शिवभान सिंह सोलंकी और कांतिलाल भूरिया का भी राज्य की राजनीति में खासी अहमियत रही.

जयस का आधार

आदिवासियों की पार्टी होने का दावा करने वाले जयश को कांग्रेस ने अपनी ओर जोड़ने की कोशिश की. जय आदिवासी युवा शक्ति नाम की इस पार्टी ने कांग्रेस से 20 सीटें अपने लिए मांग ली. हालांकि कांग्रेस ने पार्टी को सिर्फ तीन सीटें दी. अब जयस में दो धड़े दिखने लगे हैं. एक धड़ा राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरा अलावा का है जिसने कांग्रेस से तीन सीटों पर समझौता कर ही लिया है. उन्होंने और सीटें मांगने वालों को ये कह कर संतुष्ट करने का प्रयास किया है कि जिन्हें अभी टिकट नहीं मिल पाया है उन्हें अलग अलग निगमों में एडजस्ट किया जाएगा. जबकि जिन्हें टिकट नहीं मिला है, उन्होंने अलग से चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा कर रखी है. बहरहाल, निर्णायक आदिवासी मतदाताओं वाली इन 22 सीटों के साथ ही मालवा का पठार और विंध्य सतपुड़ा से घिरे इस इलाके की अनदेखी कर पाना किसी राजनीतिक दल के बस की बात नहीं है.

भाजपा-कांग्रेस में बगावत से टेंशन

भाजपा में 30 सीट पर तो कांग्रेस 47 सीटों पर बगावती तेवर...

मध्यप्रदेश विधानसभा की 230 सीटों में से कांग्रेस से एक (आमला) और भाजपा से दो विधानसभा सीट (गुना-विदिशा) के लिए उम्मीदवारों की घोषणा ही बाकी है। बाकी 228 सीटों पर उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें कांग्रेस में 42 तो भाजपा में 22 सीटों पर विरोध हो रहा है। इसके अलावा भाजपा की 6 और कांग्रेस की 5 सीटों पर खुली बगावत सामने आ रही है।

♦ **भोपाल।** विधानसभा चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के लिए बागी मुसीबत बनने वाले हैं। कई विधानसभा क्षेत्र में तो यह बागी नतीजे को भी पलटने की ताकत रखते हैं। यही कारण है कि दोनों राजनीतिक दलों के लिए बगियों को साधना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। राज्य की 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को एक चरण में मतदान होना है। राज्य में सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। दोनों ही राजनीतिक दलों को उम्मीदवार के चयन में भारी मशक्कत के दौर से गुजरना पड़ रहा है। टिकट मिलने और काटने से कई इलाकों में असंतोष भी उभर रहा है और नाराज नेता पार्टियां छोड़कर दूसरे दल का दामन थामने में लगे हैं तो वहीं विरोध प्रदर्शन करने के मामले में पीछे नहीं है। कांग्रेस अब तक 229 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है और इसके बाद लगभग दो दर्जन स्थानों से विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही है। इसी का नतीजा रहा है कि पार्टी को तीन स्थान दतिया, पिछोर व गोटेगांव से अपने उम्मीदवारों को बदलने तक पड़ गया।

बीजेपी में भी बगावत

बगावती नेताओं के समर्थक विधानसभा क्षेत्र से लेकर भोपाल तक अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है और कई ने तो पार्टी तक छोड़ दी है। भाजपा ने भी जिन उम्मीदवारों के टिकट काटे हैं और दल-बदलुओं को उम्मीदवार बनाया है उसको लेकर कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए। पार्टी से कई नेताओं ने इस्तीफा भी दिया और वर्तमान के दो विधायक शिवपुरी के कोलारस से वीरेंद्र रघुवंशी और मैहर के नारायण त्रिपाठी ने तो पार्टी को ही अलविदा कह दिया। ये दोनों ऐसे विधायक हैं जिन्हें कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद थी, मगर निराशा हाथ लगी। दोनों ही राजनीतिक दल बढ़ते असंतोष से चिंतित हैं और उन्होंने नाराज नेताओं को बनाने की जिम्मेदारी अपने-अपने दल के वरिष्ठ नेताओं को सौंपी है। वे नाराज नेताओं को भरोसा दिला रहे हैं कि राज्य में पार्टी की सरकार बनने पर उन्हें महत्व दिया जाएगा, साथ ही कई नेताओं को तो संगठन में समायोजित किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य के इस बार के चुनाव कांटे के मुकाबले के हैं। सरकार किसी भी दल की बन सकती है और यही कारण है कि तमाम दावेदार चुनाव मैदान में उतरकर अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि राजनेताओं को लगता है कि अगर वह चुनाव जीत जाते हैं तो उनकी किस्मत बदल जाएगी।

सत्ता की चाबी आने की उम्मीद

जिन नेताओं को राजनीतिक दल टिकट नहीं दे रहे हैं वे बगावत कर सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। छोटे दलों की तरफ राजनेताओं का रुझान इसलिए भी है कि अगर दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों में से किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है, वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति बनती है, तो सत्ता की चाबी उनके हाथ में आ जाएगी।

अगर सुनहरा दौर है तो आपके घर तक क्यों नहीं पहुंचा: प्रियंका गांधी

कांग्रेस सरकार गेहूं का 2600 रू. और धान का 2500 रू. समर्थन मूल्य देगी

भोपाल। अभा कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने आज दमोह में आयोजित कांग्रेस की विशाल जनसभा में अपने संबोधन की शुरूआत करते हुये कहा कि भाइयो-बहनो मुझे पता है आप बहुत समय से हमारा इंतजार कर रहे हैं और इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। भगवान जागेश्वर नाथ जी की जय, आज वाल्मीकि जी की जयंती है, मैं उन्हें प्रणाम करती हूं। बुंदेलखंड की धरती रानी दुर्गावती की धरती है बुंदेलखंड के वीरों ने 1857 से लेकर आजादी की लड़ाई तक बलिदान दिए उन्हें नमन करती हूं।

प्रियंका गांधी ने कहा कि आज सरकार बता रही है कि देश का सुनहरा दौर आ गया है लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं कि यह सुनहरा दौर आपकी चौखट तक क्यों नहीं पहुंचा, आपके जीवन में क्यों नहीं पहुंचा है? आप तो गरीब के गरीब हैं आप अपने जीवन के संघर्षों में जूझ रहे हैं आपके घरों में और दमोह में आज भी पानी की किल्लत है। आज लोग बुंदेलखंड से पलायन क्यों कर रहे हैं? भाजपा ने 18 साल महिलाओं को बेवकूफ बनाया और चुनाव से दो महीने पहले स्कीम लेकर आ गये लेकिन उनकी झूठ की गारंटी अब नहीं चलने वाली हैं। क्योकि अब मप्र में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और हमारी गारंटी पर इसलिए भरोसा कीजिए, क्योंकि कमलनाथ जी ने 15 महीने में गारंटियां पूरी करके दिखायी, कांग्रेस सरकारों ने हिमाचल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू की, कांग्रेस की सरकार बनने पर मप्र में भी होगी, कांग्रेस सरकार गेहूं का 2600 रू और धान का 2500 रू. समर्थन मूल्य देगी।

प्रियंका गांधी ने कहा कि कमलनाथ जी ने आपको बताया है कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने बुंदेलखंड पैकेज देने का काम किया था, लेकिन आज मैं यहां मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर आपके बीच में आई हुई हूं। आज नेताओं के आरोप-प्रत्यारोप के बीच आपको निर्णय लेना है कि आप किसका समर्थन करेंगे। मैं यहां बातें करने आई हूं ना की भाषण देने। एक जमाना था जब हमारे देश में बड़े-बड़े महापुरुष आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी उनसे बहुत उम्मीदें थी आज आपकी भी उम्मीदें होनी चाहिए किसी दल से, किसी नेता से।

प्रियंका गांधी ने कहा कि जब मैं आम जनता से मिलती हूं और उनसे पूछती हूं कि आपकी क्या उम्मीद है सरकार से, तो वह बताते हैं कि हमारे संघर्ष भरे जीवन में हम चाहते हैं कि बस थोड़ा सी मदद मिल जाए सरकार की ओर से, हमें रोजगार मिल जाए, हमें महंगाई से राहत मिल जाए, हमें सुरक्षा मिल जाए, बस इतनी सी उम्मीद जनता की रहती है। मुझे भी पता है कि आप लोग रात दिन मेहनत करते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और मुझे यह भी पता है कि बुंदेलखंड से पलायन बहुत होता है। आप जो यह मेहनत करते हैं आप भी चाहते होंगे कि आपका भविष्य मजबूत हो, सुरक्षित हो और आप भी चाहते हैं कि सरकार आपके जीवन में भागीदारी निभाएं और मदद करें।

प्रियंका गांधी ने कहा कि पलायन तभी होता है जब क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं नहीं होती है और आपने क्या कभी सोचा है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज देश और इस प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की 18 साल की सरकार ने पिछले 3 सालों में मात्र 21 नौकरियां दी है। मध्य प्रदेश में कितनी सरकारी नौकरियां खाली हैं, कितने पद खाली पड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर के पद खाली हैं। लेकिन फिर भी सरकार इन पदों पर भर्ती करने का काम नहीं कर रही है। आज मध्य प्रदेश में युवाओं ने भर्ती के लिए फार्म भरे हैं, परीक्षा पास की, लेकिन फिर भी उनके हाथ में रोजगार नहीं है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि बड़े-बड़े पीएसयू और सरकारी योजनाओं और विभागों से भारी मात्रा में रोजगार बनते थे, लेकिन ये सरकार अपने मित्रों को सभी पीएसयू बेचने का काम कर रही है। छोटे दुकानदारों, छोटे व्यापारों से रोजगार बनते थे, लेकिन सरकार ने उन सभी की कमर तोड़ रखी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय और उसके बाद भी अन्य देशों की सरकारों ने नागरिकों की आर्थिक मदद की, व्यापारियों और छोटे व्यापारियों की भी मदद की। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला।

प्रियंका गांधी ने कहा कि आज बड़े-बड़े उद्योगपतियों को देश की संपत्ति बेचने का काम यह सरकार कर रही है, किसानों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। डीजल, पेट्रोल, खाद, बिजली, पानी सब कुछ इन्होंने महंगा कर रखा है। किसानों को किसी भी तरीके की राहत देने का काम यह सरकार नहीं करना चाहती है और इस तरह से लगातार महंगाई एकतरफा बढ़ती जा रही है, रोजगार के माध्यम बंद होते जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आपके जीवन में बहुत संघर्ष है, आप अपने बच्चों के लिए बचत करना चाहते हैं, उन्हें पढ़ाना चाहते हैं लेकिन हर चीज पर इतना ज्यादा टैक्स है की बचत तो छोड़िये गुजारा करना भी मुश्किल है, अगर किताबें खरीदनी है तो वहां पर भी जीएसटी देनी पड़ रही है, बच्चों की यूनिफार्म के लिए भारी जीएसटी देनी पड़ रही है। अपने स्वास्थ्य के लिए दवाइयां खरीदनी है तो वहां पर भी हमें जीएसटी देकर महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आप आगे पढ़ कैसे पाएंगे, क्योंकि एक ओर इतनी महंगाई, बेरोजगारी है और दूसरी ओर सरकार भी कोई मदद नहीं कर रही है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि आज सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की केवल एक ही मांग है उनकी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। आपकी इन मांगों पर आज की सरकार कहती है कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन दूसरी ओर अडानी जी के कर्ज को माफ करने के लिए सरकार के पास पैसे हैं। इस सरकार के पास किसानों का कर्ज माफ करने के लिए भी पैसे नहीं है। आज ये सरकार केवल इवेंट करती है और बताती है कि बड़े-बड़े काम हो रहे हैं। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं कि पिछले 18 साल से भाजपा की सरकार आपके प्रदेश में है, क्या आपके जीवन में कोई बड़ी तरक्की हुई है? क्या आपको रोजगार मिला है? क्या महंगाई घटी है? आज देश में जो सरकार चल रही है वह बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। आज इस सरकार के पास गरीबों के लिए किसानों के लिए युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि जो हम जनगणना की बात करते हैं, इस देश में ओबीसी वर्ग, अनसूचित जाति और दलित वर्ग के लोग कितने हैं? आप आज देखेंगे कि देश के सभी बड़े मीडिया संस्थान, सभी यूनिवर्सिटी और सभी सरकारी संस्थानों में ओबीसी वर्ग और एससी, एसटी वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है। जब हम जातिगत जनगणना करने की बात करते हैं और न्याय देने की बात करते हैं तो यह सरकार यह काम नहीं करना चाहती है, बल्कि बड़े-बड़े इवेंट करके और मीडिया के माध्यम से आप सभी को बताती है कि हम ओबीसी के लिए, हम दलित के लिए, हम आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल अच्छे कालेज और स्वास्थ्य की सुविधा क्यों नहीं है? 18 साल की मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के पास क्या अब कोई बहाना बचता है, लेकिन फिर भी आज भाजपा के नेता जनता के बीच में जाकर झूठी घोषणाएं करते हैं। भाजपा नेता समझ चुके हैं कि चुनाव के समय पर खोखली घोषणाएं कर दो, धर्म की बात कर लो, जाति की बात कर लो और चुनाव जीतने की जो नैया है वह पार हो जाएगी। इसलिए भाजपा काम करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही उनकी नियत काम करने की है।

प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की हमारी कांग्रेस सरकार ने जनता की संपत्ति को जनता के रोजगार के लिए उपयोगी बनाने का काम किया है, छत्तीसगढ़ में किसानी के रोजगार को बढ़ावा दिया गया है और लोग अब वापस कृषि से संबंधित रोजगार कर रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार बनी, वह आप सभी के हित की सरकार है और ऐसा ही काम हम मध्य प्रदेश में करने वाले हैं। कांग्रेस की राजनीति काम करने की राजनीति है, जबकि भाजपा की झूठ और शर्मिंदगी वाली राजनीति है।

उन्होंने कहा कि मैं आज आपके सामने केवल यही कहने आई हूं आपको सही प्रयासों से, सही नतीजे पर पहुंचना है और सही सरकार बनाकर मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करना है। आपको कांग्रेस के वचन बताने से पहले यह भी कहना चाहती हूं कि आप देखिए कांग्रेस की सरकार जहां पर है, वहां पर हम अपने वचन पत्रों का पालन कर रहे हैं। कांग्रेस के वचन सरकार बनते ही लागू होना शुरू हो जाते हैं भाजपा की तरह नहीं कि जब 18 साल सत्ता में निकल गए, अब आखिरी में इन्हें लाडली बहन याद आई। आज मध्य प्रदेश में हर दिन 17 बलात्कार हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन चुनाव के 2 महीने पहले लाडली बहन योजना के जरिए महिलाओं को गुमराह करना चाहते हैं। मैं महिलाओं से कहना चाहती हूं कि आप सभी की बात सुनो, लेकिन आप वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए करो।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर गेहूं और धान का समर्थन मूल्य 2600 और 2500 रू करने का काम करेंगे, जिसे हम 3000 रूपये तक लेकर जायेंगे, 100 यूनिट बिजली बिल माफ करने का काम करेंगे। हम गैस का सिलेंडर 500 में देने का काम करेंगे, स्कूली शिक्षा के लिए स्कूल के बच्चों को हम 500 से 1500 रू. देने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार के 220 घोटाले हमारे सामने हैं। भाजपा शासन और अंग्रेजी शासन में कोई अंतर नहीं बचा है। मैं आज दमोह की धरती पर आपसे वोट मांगने नहीं आई हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप सोच विचार करके 17 तारीख को वोट देने जाएंगे तो वोट तो आप कांग्रेस को ही वोट करेंगे ही और हमारे वचन पत्र को ध्यान में रखकर जब आप वोट करेंगे तो अपने आगे आने वाली पीढ़ियों और प्रदेश के भविष्य को भी सुरक्षित करने का काम करेंगे और अपने बुंदेलखंड को सुरक्षित रखने का काम भी करेंगे।

साप्ताहिक समय माया

भ्रष्टों की फौज सूचना अधिकार में इसलिए जानकारी नहीं देती

वाणिज्य कर में खरीदी व स्क्रेप बिक्री में मोटी दलाली हजम

मुख्यालय भ्रष्टाचारियों और जालसाजों का अड्डा

बहुराष्ट्रीय कंपनी के इशारे पर लगाया गया जीएसटी में अब केवल आयुक्त प्रधान सचिव मुख्यमंत्री मंत्री को सीधा कमीशन मिल जाता है इसलिए वह शासकीय और राजस्व को हानि पहुंचाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती और यही कारण है पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश की वाणिज्य कर की 6 एंटी विजन ब्यूरो को धारा 68, 71 में माल वाहक पकड़ने के अधिकार नहीं दिए जा रहे इसके साथ ही जीएसटी के मूल कर में में धारा 68, 71 के अंतर्गत प्रदेश के प्रवेश द्वार पर जांच करने के लिए प्रदेश के 40 से ज्यादा नाको को नहीं खोला जा रहा। क्योंकि अब बाजार में अधिकांश पैकेज माल जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गांव की दुकानों से लेकर शहरों की गली मोहल्ले की दुकानों पर उन्हें का माल बिकता है और वही माल जिसमें अधिकांश में टैक्स चोरी होती है और आप जानते हैं उस धूर्त जाहिल मोदी ने अडानी के जीएसटी को माफ कर दिया। जबकि टाटा बिरला अंबानी डी मार्ट मित्तल आईटीसी यूनि लीवर से सीधा ही ऊपर लेवल पर कमीशन बढ़ जाता है इसलिए ना ही नाकों को खोलकर वहां स्टाफ बैठ कर चेकिंग करने की पावर दिए गए नाही धारा 68, 71 में वाहनों की जांच करने के कर अपवंचन ब्यूरो को पावर दिए जा रहे हैं।

दूसरी तरफ केंद्रीय माल एवं सेवा कर विभाग जो पूर्व में कस्टम और एक्साइज हुआ करता था। वर्दी पहनकर न केवल माल वाहकों को पकड़ता है। घर की वसूली करने के साथ ऊपर से अपनी भारी मोटी भ्रष्टाचार की वसूली भी करता है। वहां सबको खुली छूट है माल वाहकों को पकड़ने से लेकर छापे मारने, गोदाम की जांच करने, दुकानों फैक्ट्री में उनके स्टॉक और खाते भाई की जांच करने की पूरी छूट होने के कारण कारण वह सपना केवल जांच करते हैं करके वसूली करते हैं और ऊपर से मोती वसूली करने के साथ न मिलने पर वह माल और मालवाहकों के मालिकों की पिटाई भी करते हैं।

दूसरी तरफ जो भी विभाग में नया आयुक्त आता है वह अपनी मोटी कमाई के लिए हरामखोर मोटा कमीशन खाने भारी मोटी खरीदी करता है। और हाल ही में पूरे विभाग में लगभग 400 से ज्यादा कंप्यूटर प्रिंटर की खरीदी लगभग 40% कमीशन पर की गई जबकि पुराने कंप्यूटर प्रिंटर मॉनिटर सब अच्छी हालत में काम कर रहे थे परंतु मोटी खरीदी और अब वर्तमान में आप जानते हैं की कंप्यूटर से ज्यादा महंगे उसमें डाले जा रहे सॉफ्टवेयर की खरीदी में पैसा खर्च होता है। खरीदे गए। यही कारण है कि वहां बैठे जाल साज हरामखोरों को सूचना के अधिकार में पत्र देने पर उन पत्रों को जवाब देने के नाम पर आधी अधूरी की जानकारी देकर अपील में आने के लिए व्यवस्था करते हैं और अपील लगाने पर वहां बैठे वरिष्ठ अधिकारी उन अभिनव पर घुमा फिरा कर जवाब देकर उलझा देते हैं जबकि विवाह का मुख्यालय यहां पर है 18 साल गुजर जाने के बाद भी इन जलसा जो नहीं अपने भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4 में के 17 बिंदुओं के साथ आठ बिंदु और जोड़े गए हैं 25 बिंदुओं की जानकारी अभी तक अपनी सीटों पर सार्वजनिक रूप से देखने अवलोकन करने के लिए उपलब्ध नहीं करवाई हाल ही में इंदौर के संभाग क्रमांक 2 में बेंचीनी के नाम पर लाखों रुपए बीच में हजम कर लिए सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर जिन तीन बिंदुओं की जानकारी दी गई के साथ एक बिंदु आपने जो निविदा मां की बिक्री के लिए जारी की थी उसमें कितने निविदाएं आई किसने कितनी डर भारी उसकी प्रतियोगात्मक जड़ों की जानकारी निविदाओं की जानकारी के बिंदुओं की जानकारी और हरामखोर उपयुक्त सहायक आयुक्त नहीं दी अपील में जाने पर भी उनका अपनी गर्दन फंस रही थी इसलिए उन्होंने उसको भी अटका दिया जैसे सब इनके बाप की जागीर हो इस फर्जी बड़े का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है की माल स्क्रैप माल की बिक्री का आदेश पूरे प्रदेश के लिए 16 9 2022 को तन्वी हुड्डा अपर आयुक्त वाणिज्य कर मुख्यालय इंदौर से जारी हुआ। परंतु टेंडर की विज्ञप्ति 2 मई 2022 को दैनिक दोपहर में प्रकाशित कर दी गई थी नई दुनिया में वह दैनिक शांति 6:00 उ.रु. को 1 मईको प्रकाशित करवा दी गई थी जब किसके पूर्व में है निविदा छह समाचार पत्रों में दैनिक जागरण नवभारत भोपाल नई दुनिया दैनिक सांध्य 6:00 पीएम, स्टेट एक्सप्रेस में 21 जुलाई 2021 को प्रकाशित करवा दी गई थी।

इसके पूर्व में भी नई दुनिया इंदौर में 14 अप्रैल 22 पत्रिका में 15 अप्रैल 22 को निविदायें प्रकाशित करवाई गई थी। अर्थात जीतने का माल नहीं था उससे दोगुना पैसा प्रकाशन में खर्च किया गया।

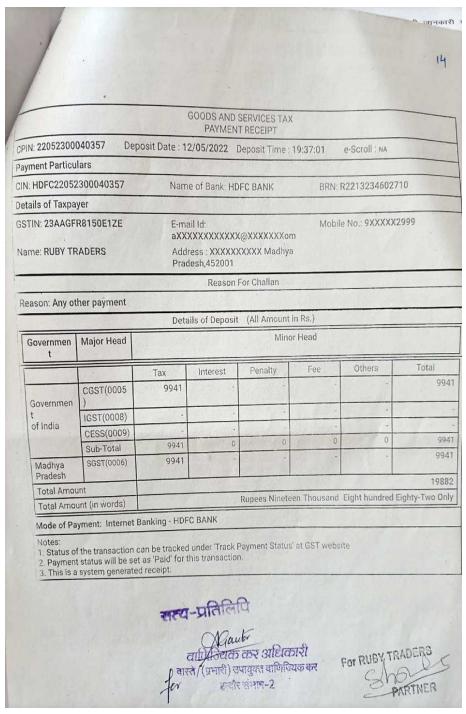

इस संभाग में 5 वाणिज्य कर वृत्तों की सामग्री एकत्रित करके बेची गई और इस सारे लाखों की कमीशन में एक बाबू की भी भूमिका बताई जाती है। यह सामग्री में रूबी ट्रेडर्स नयापुरा इंदौर को 12 मई 2022 को ही बेंच दी गई थी। जिसका पैसा उसने दो चालान से रू1,17, 337/- व 19882/- जमा करवाया। अनुपयोगी लोहे की सामग्री में कबाड़ बनाया गया लोहे का फर्नीचर टेबल कुर्सियां अलमारियों व अन्य सामग्री थी लकड़ी की सामग्री में भी पुरानी टेबल कुर्सियां अलमारियां आदि कबाड़ बनाई गई थीं। अनुपयोगी प्लास्टिक सामग्री में चालू कंप्यूटर प्रिंटर मॉनिटर आदि थे पर नये खरीद लेने के कारण सब कबाड़ बना मोटे कमीशन पर बेंच दिये गये। ऐसे ही चालू कंप्यूटर मॉनिटर प्रिंटर यूनिक इको रीसायकल, ने 26 अप्रैल 2023 को एक चालान 4712 का, दूसरा चलन 26175 का भरा परंतु उसको कितना माल में क्या-क्या दिया गया। इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई।

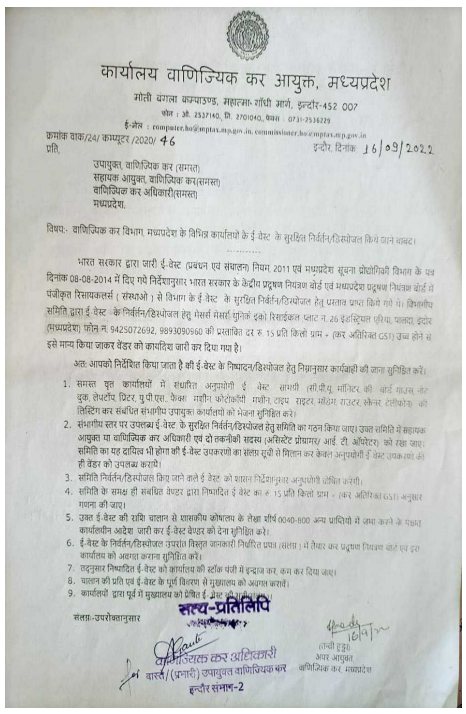

जब इसी से संबंधित यही जानकारी इंदौर के संभाग क्रमांक 1 व 3 में भी मांगी गई। तो अपर आयुक्त के पत्र के बाद संभाग 3 में इसके लिए पूरी एक समिति बनाई गई। जो यह निर्णय लेने के लिए की कौन सा सामान खराब है और कबाड़ हो चुकने के कारण बेचने योग्य है। परंतु संभाग क्रमांक 2 में क्योंकि भारी जल सजनिया की गई थी इसलिए इसमें कोई समिति की नियुक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उस समिति में कौन-कौन से सदस्य थे जिन्होंने यह निर्णय लिया की कौन सा सामान कबाड़ हो चुका है। उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता और बेंचने योग्य है। जबकि समान बिक्री के लिए कोरोना कल से पहले से ही कबाड इकट्ठा किया जा रहा था। धीरे-धीरे मोती बंगले में वह सामान बाहर पड़ा हुआ था। जो जरूरत के हिसाब से बेचा भी जाता रहा। इस जालसाजी में मुख्यालय पड़ोस में होने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया और वह शातिर बाबू अपना खेल करता रहा आखिर यही कारण था कि वहां बैठे उपायुक्त और सहायक आयुक्त नहीं जलसा जी कर पूरी जानकारी देने में भी षड्यंत्र किया।

जहां तक कमीशन खोरी का सवाल है तो चेतक चेंबर में लगभग 14 व्रत्तों के कार्यालयों के साथ दो संभागीय आयुक्त दो संभागीय अपील आयुक्त अपर आयुक्त के कार्यालय सन 2000 से किराए के भवन में चल रहे हैं। वर्तमान में जिन का किराया लगभग 40 करोड रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा है पिछले 12 15 वर्षों से लगातार उसे अनुबंध की कॉपी साल भर में दिए जा रहे किराए के भुगतान की कॉपी मांगने के बाद में भी वहां बैठ हरामखोरो ने हीं उसकी कॉपियां नहीं दी क्योंकि मोटा कमीशन जो लगभग 30 से 40% है जिसमें वहां बैठे आयुक्त का हिस्सा भी है। नहीं दी जा रही है। शायद इनके बाप की जागीर है। जो यह राज नहीं खोल सकती दूसरी तरफ अफीम गोदाम की 5 एकड़ से ज्यादा पड़ी हुई जमीन को जानबूझकर इसलिए बर्बाद किया जा रहा है कई कर्मचारियों ने वहां स्थाई निवास बना लिए खाली करने की बात करने पर बिजली कट्टी कर दी गई और अधिकारियों का अपमान करके भगा दिया गया जबकि बड़ी से बड़ी कालोनियां मकान भवन तोड़ दिए जाते हैं पर उसे जमीन का पूरा कब्जा लेकर मन भावन नहीं बनाया जा रहा क्योंकि भवन बन जाने के बाद वहां बैठे संभाग तीन के उपायुक्त के साथ विभाग के आयुक्त को कमीशन कैसे मिलेगा जबकि चेतक चेंबर में आग लग चुकी है पूरा भवन लगभग 30 साल पुराना हो चुका है परंतु उसे 5 एकड़ जमीन का कब्ज और सारे प्रकरण इसलिए समाप्त नहीं करवाई जा रहे ताकि सबका कमीशन हर महीने मिलता बना रहा है। आखिर जनता से लूटा पैसा अधिकारियों के बाप की जागीर है जो हजम करते रहेंगे और स्वयं का भवन न बनाकर लूटा हुआ धन लूट कर मोटा कमीशन हजम करते रहेंगे।

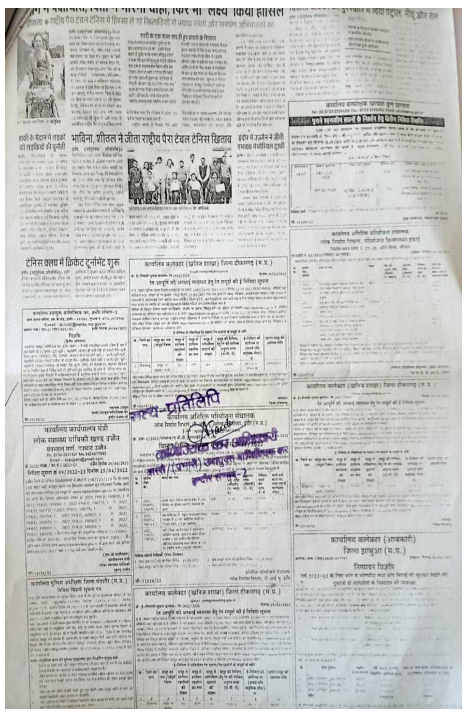

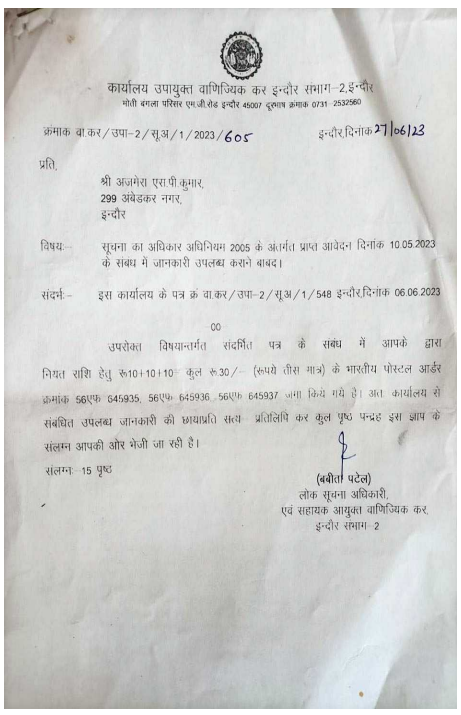

GOODS AND SERVICES TAX
PAYMENT RECEIPT
Name: RUBY TRADERS
सत्य-प्रतिलिपि
For RUBY TRADERS
PARTNER

कार्यालय वाणिज्यिक कर आयुक्त, मध्यप्रदेश
सत्य-प्रतिलिपि

सत्य-प्रतिलिपि

कार्यालय उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर संभाग-2 इन्दौर
प्रति
श्री अजमेरा एस.पी.कुमार,
299 अवेडकर नगर,
इन्दौर
(बबीता पटेल)
लोक सूचना अधिकारी,
एवं सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर
इन्दौर संभाग-2

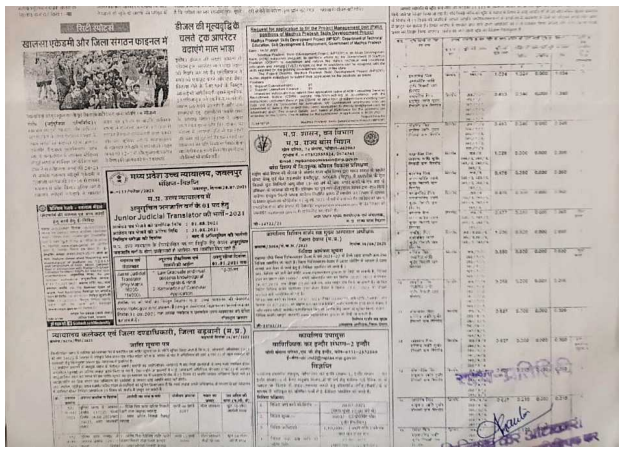

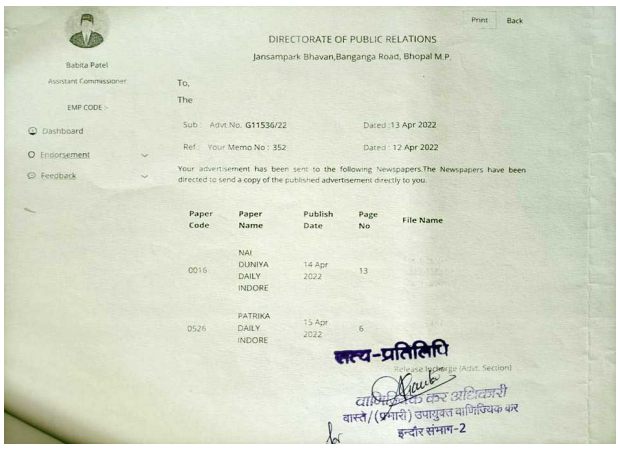

DIRECTORATE OF PUBLIC RELATIONS
Jansampark Bhavan,Banganga Road, Bhopal M.P.

Babita Patel
Assistant Commissioner
EMP CODE :-
Dashboard
Endorsement
Feedback

Print Back

To,
The

Sub : Advt.No. G11536/22 Dated :13 Apr 2022
Ref : Your Memo No : 352 Dated : 12 Apr 2022

Your advertisement has been sent to the following Newspapers.The Newspapers have been directed to send a copy of the published advertisement directly to you.

Paper Code	Paper Name	Publish Date	Page No	File Name
0016	NAI DUNIYA DAILY INDORE	14 Apr 2022	13	
0526	PATRIKA DAILY INDORE	15 Apr 2022	6	

Release Incharge (Advt. Section)

सत्य-प्रतिलिपि
वाणिज्यिक कर अधिकारी
वास्ते/(प्रभारी) उपायुक्त वाणिज्यिक कर
इन्दौर संभाग-2

2 May 2022

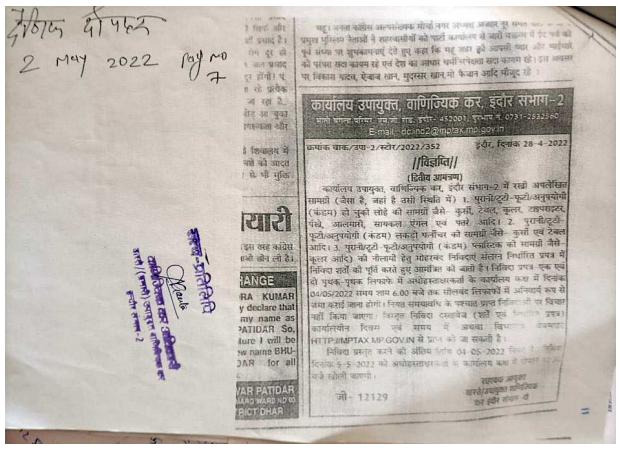

कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर संभाग-2

जी- 12129

13

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

(Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	
Depositor/Dealer Name	RUBY TRADERS
Address	141, NAYAPURA, INDORE, Indore, Madhya Pradesh - 452003
District selected for Payment	Indore
Unique Registration Number (URN)	MPTURN120520220014282
Department and Office Name	Commercial Tax, RUBY TRADERS
Challan Payment Period	2022-2023

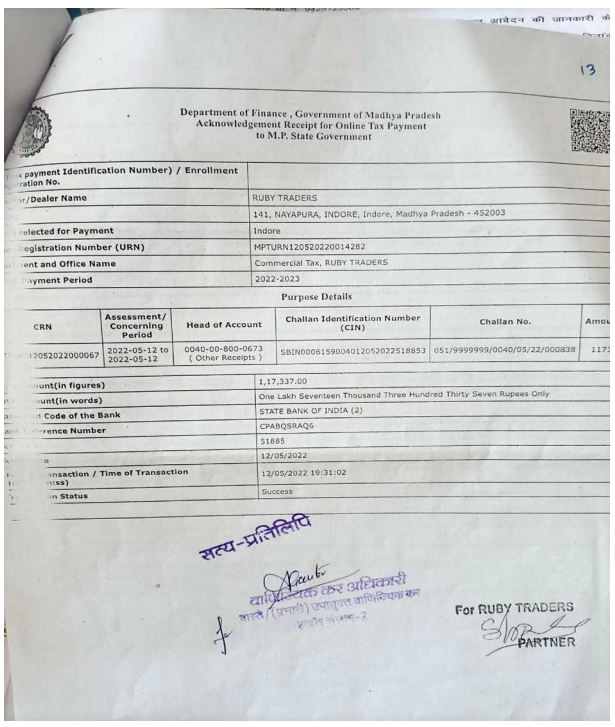

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount
12052022000067	2022-05-12 to 2022-05-12	0040-00-800-0673 (Other Receipts)	SBIN00061590040120520225 18853	051/9999999/0040/05/22/000838	117[illegible]

Total Amount(in figures)	1,17,337.00
Total Amount(in words)	One Lakh Seventeen Thousand Three Hundred Thirty Seven Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	CPABQSRAQ6
Scroll No	51885
Scroll Date	12/05/2022
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	12/05/2022 19:31:02
Transaction Status	Success

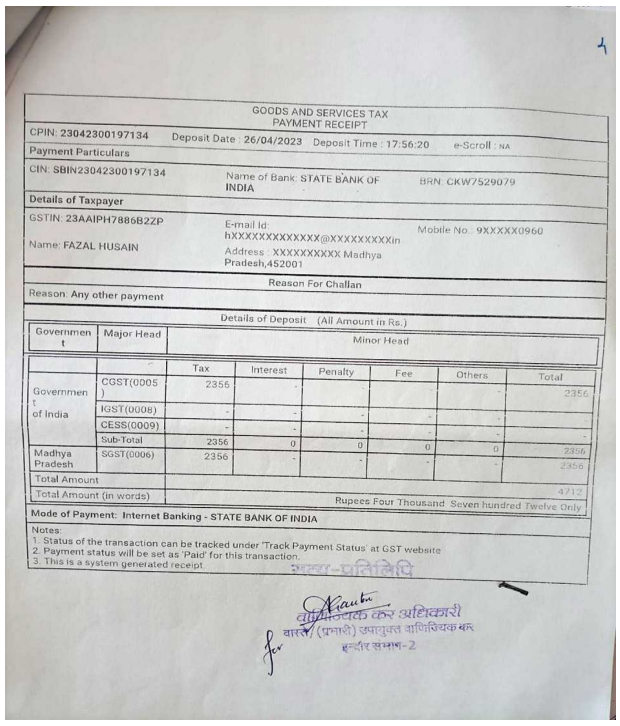

सत्य-प्रतिलिपि
वाणिज्यिक कर अधिकारी
वास्ते/(प्रभारी) उपायुक्त वाणिज्यिक कर
इन्दौर संभाग-2

For RUBY TRADERS
PARTNER

GOODS AND SERVICES TAX
PAYMENT RECEIPT

CPIN: 23042300197134 Deposit Date : 26/04/2023 Deposit Time : 17:56:20 e-Scroll : NA

Payment Particulars
CIN: SBIN23042300197134 Name of Bank: STATE BANK OF INDIA BRN: CKW7529079

Details of Taxpayer
GSTIN: 23AAIPH7886B2ZP E-mail Id: hXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXin Mobile No.: 9XXXXX0960
Name: FAZAL HUSAIN Address : XXXXXXXXXX Madhya Pradesh,452001

Reason For Challan
Reason: Any other payment

Details of Deposit (All Amount in Rs.)

Government	Major Head	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
Government of India	CGST(0005)	2356	-	-	-	-	2356
	IGST(0008)	-	-	-	-	-	-
	CESS(0009)	-	-	-	-	-	-
	Sub-Total	2356	0	0	0	0	2356
Madhya Pradesh	SGST(0006)	2356	-	-	-	-	2356
Total Amount							4712
Total Amount (in words)							Rupees Four Thousand Seven hundred Twelve Only

Mode of Payment: Internet Banking - STATE BANK OF INDIA

Notes:
1. Status of the transaction can be tracked under 'Track Payment Status' at GST website
2. Payment status will be set as 'Paid' for this transaction.
3. This is a system generated receipt.

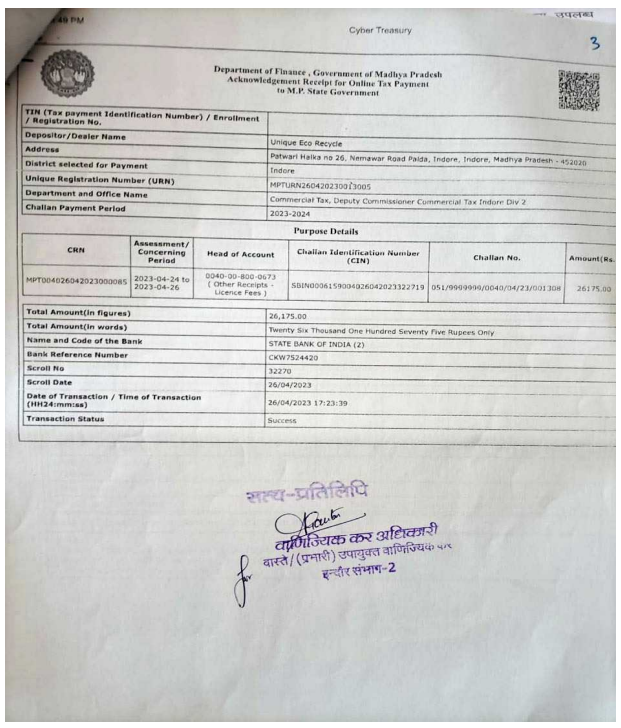

सत्य-प्रतिलिपि
वाणिज्यिक कर अधिकारी
वास्ते/(प्रभारी) उपायुक्त वाणिज्यिक कर
इन्दौर संभाग-2

Cyber Treasury

3

Department of Finance , Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.	
Depositor/Dealer Name	Unique Eco Recycle
Address	Patwari Halka no 26, Nemawar Road Palda, Indore, Indore, Madhya Pradesh - 452020
District selected for Payment	Indore
Unique Registration Number (URN)	MPTURN260420230013005
Department and Office Name	Commercial Tax, Deputy Commissioner Commercial Tax Indore Div 2
Challan Payment Period	2023-2024

Purpose Details

CRN	Assessment/ Concerning Period	Head of Account	Challan Identification Number (CIN)	Challan No.	Amount(Rs.
MPT004026042023000085	2023-04-24 to 2023-04-26	0040-00-800-0673 (Other Receipts - Licence Fees)	SBIN00061590040260420233 22719	051/9999999/0040/04/23/001308	26175.00

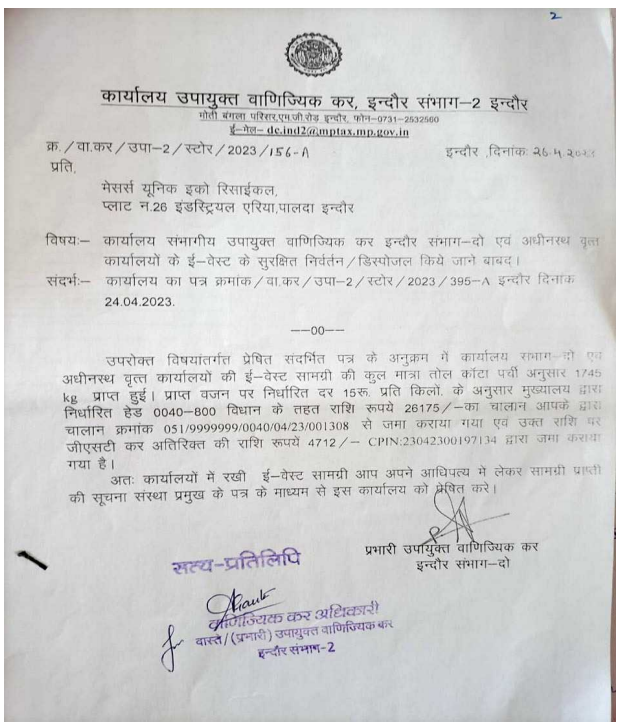

Total Amount(in figures)	26,175.00
Total Amount(in words)	Twenty Six Thousand One Hundred Seventy Five Rupees Only
Name and Code of the Bank	STATE BANK OF INDIA (2)
Bank Reference Number	CKW7524420
Scroll No	32270
Scroll Date	26/04/2023
Date of Transaction / Time of Transaction (HH24:mm:ss)	26/04/2023 17:23:39
Transaction Status	Success

सत्य-प्रतिलिपि
वाणिज्यिक कर अधिकारी
वास्ते/(प्रभारी) उपायुक्त वाणिज्यिक कर
इन्दौर संभाग-2

2

कार्यालय उपायुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर संभाग–2 इन्दौर
मोती बंगला परिसर,एम.जी.रोड इन्दौर, फोन–0731–2532560
ई–मेल– dc.ind2@mptax.mp.gov.in

क्र. / वा.कर / उपा–2 / स्टोर / 2023 / 156-A इन्दौर ,दिनांक 26.5.2023

प्रति,
मेसर्स यूनिक इको रिसाईकल,
प्लाट न.26 इंडस्ट्रियल एरिया,पालदा इन्दौर

विषयः– कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर इन्दौर संभाग–दो एवं अधीनस्थ वृत्त कार्यालयों के ई–वेस्ट के सुरक्षित निर्वर्तन / डिस्पोजल किये जाने बावद।

संदर्भः– कार्यालय का पत्र क्रमांक / वा.कर / उपा–2 / स्टोर / 2023 / 395–A इन्दौर दिनांक 24.04.2023.

––00––

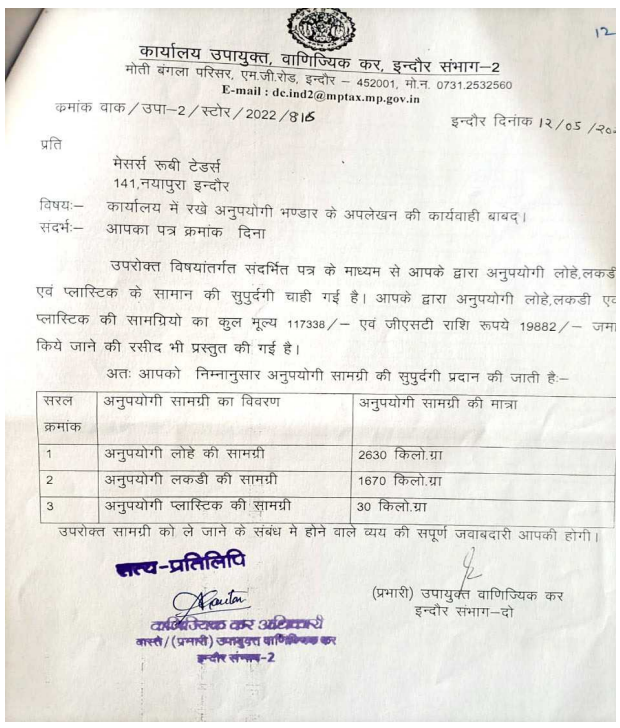

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रेषित संदर्भित पत्र के अनुक्रम में कार्यालय संभाग–दो एवं अधीनस्थ वृत्त कार्यालयों की ई–वेस्ट सामग्री की कुल मात्रा तोल कॉटा पर्ची अनुसार 1745 kg प्राप्त हुई। प्राप्त वजन पर निर्धारित दर 15रू. प्रति किलों. के अनुसार मुख्यालय द्वारा निर्धारित हेड 0040–800 विधान के तहत राशि रूपये 26175 /–का चालान आपके द्वारा चालान क्रमांक 051/9999999/0040/04/23/001308 से जमा कराया गया एवं उक्त राशि पर जीएसटी कर अतिरिक्त की राशि रूपयें 4712 /– CPIN:23042300197134 द्वारा जमा कराया गया है।

अतः कार्यालयों में रखी ई–वेस्ट सामग्री आप अपने आधिपत्य मे लेकर सामग्री प्राप्ती की सूचना संस्था प्रमुख के पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करे।

प्रभारी उपायुक्त वाणिज्यिक कर
इन्दौर संभाग–दो

सत्य-प्रतिलिपि
वाणिज्यिक कर अधिकारी
वास्ते/(प्रभारी) उपायुक्त वाणिज्यिक कर
इन्दौर संभाग-2

12

कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर संभाग–2
मोती बंगला परिसर, एम.जी.रोड, इन्दौर – 452001, मो.न. 0731.2532560
E-mail : dc.ind2@mptax.mp.gov.in

कमांक वाक / उपा–2 / स्टोर / 2022 / 816 इन्दौर दिनांक 12/05/20[illegible]

प्रति
मेसर्स रूबी टेडर्स
141,नयापुरा इन्दौर

विषयः– कार्यालय में रखे अनुपयोगी भण्डार के अपलेखन की कार्यवाही बाबद्।
संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक दिना

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा अनुपयोगी लोहे,लकडी एवं प्लास्टिक के सामान की सुपुर्दगी चाही गई है। आपके द्वारा अनुपयोगी लोहे,लकडी एवं प्लास्टिक की सामग्रियो का कुल मूल्य 117338 /– एवं जीएसटी राशि रूपये 19882 /– जमा किये जाने की रसीद भी प्रस्तुत की गई है।

अतः आपको निम्नानुसार अनुपयोगी सामग्री की सुपुर्दगी प्रदान की जाती हैः–

सरल क्रमांक	अनुपयोगी सामग्री का विवरण	अनुपयोगी सामग्री की मात्रा
1	अनुपयोगी लोहे की सामग्री	2630 किलो.ग्रा
2	अनुपयोगी लकडी की सामग्री	1670 किलो.ग्रा
3	अनुपयोगी प्लास्टिक की सामग्री	30 किलो.ग्रा

उपरोक्त सामग्री को ले जाने के संबंध मे होने वाले व्यय की सपूर्ण जवाबदारी आपकी होगी।

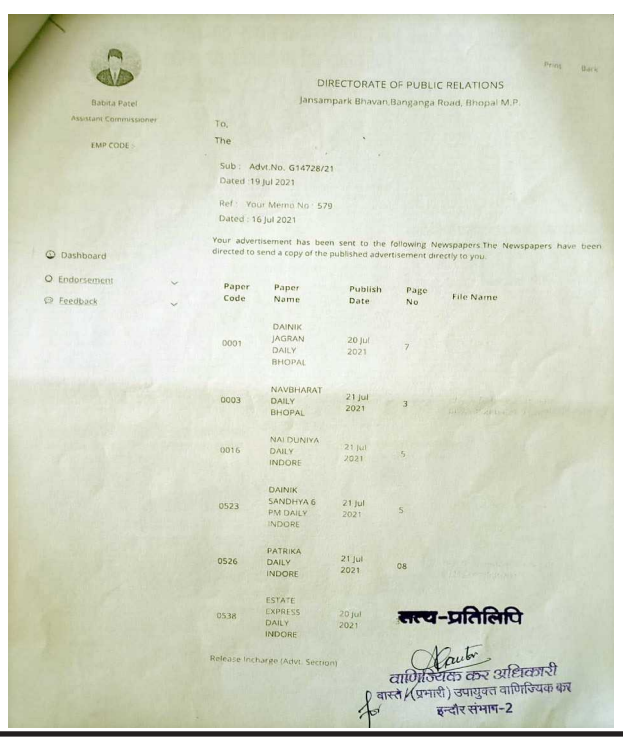

(प्रभारी) उपायुक्त वाणिज्यिक कर
इन्दौर संभाग–दो

सत्य-प्रतिलिपि
वाणिज्यिक कर अधिकारी
वास्ते/(प्रभारी) उपायुक्त वाणिज्यिक कर
इन्दौर संभाग-2

DIRECTORATE OF PUBLIC RELATIONS
Jansampark Bhavan,Banganga Road, Bhopal M.P.

Babita Patel
Assistant Commissioner
EMP CODE :-
Dashboard
Endorsement
Feedback

Print Back

To,
The

Sub : Advt.No. G14728/21
Dated :19 Jul 2021
Ref : Your Memo No : 579
Dated : 16 Jul 2021

Your advertisement has been sent to the following Newspapers.The Newspapers have been directed to send a copy of the published advertisement directly to you.

Paper Code	Paper Name	Publish Date	Page No	File Name
0001	DAINIK JAGRAN DAILY BHOPAL	20 Jul 2021	7	
0003	NAVBHARAT DAILY BHOPAL	21 Jul 2021	3	
0016	NAI DUNIYA DAILY INDORE	21 Jul 2021	5	
0523	DAINIK SANDHYA 6 PM DAILY INDORE	21 Jul 2021	5	
0526	PATRIKA DAILY INDORE	21 Jul 2021	08	
0538	ESTATE EXPRESS DAILY INDORE	20 Jul 2021	[illegible]	

Release Incharge (Advt. Section)

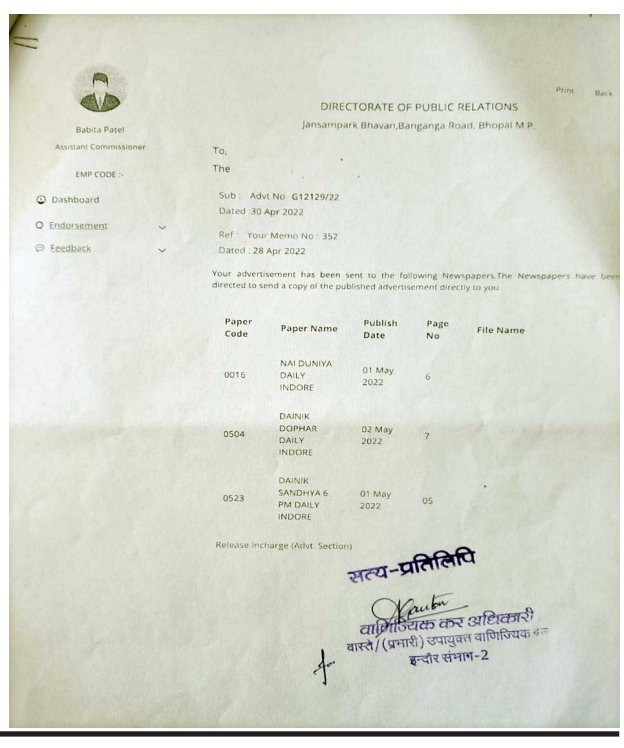

सत्य-प्रतिलिपि
वाणिज्यिक कर अधिकारी
वास्ते/(प्रभारी) उपायुक्त वाणिज्यिक कर
इन्दौर संभाग-2

DIRECTORATE OF PUBLIC RELATIONS
Jansampark Bhavan,Banganga Road, Bhopal M.P.

Babita Patel
Assistant Commissioner
EMP CODE :-
Dashboard
Endorsement
Feedback

Print Back

To,
The

Sub : Advt.No G12129/22
Dated :30 Apr 2022
Ref : Your Memo No : 352
Dated : 28 Apr 2022

Your advertisement has been sent to the following Newspapers.The Newspapers have been directed to send a copy of the published advertisement directly to you.

Paper Code	Paper Name	Publish Date	Page No	File Name
0016	NAI DUNIYA DAILY INDORE	01 May 2022	6	
0504	DAINIK DOPHAR DAILY INDORE	02 May 2022	7	
0523	DAINIK SANDHYA 6 PM DAILY INDORE	01 May 2022	05	

Release Incharge (Advt. Section)

सत्य-प्रतिलिपि
वाणिज्यिक कर अधिकारी
वास्ते/(प्रभारी) उपायुक्त वाणिज्यिक कर
इन्दौर संभाग-2

साप्ताहिक समय माया

मप्र में 17, राजस्थान में 23, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को मतदान, नतीजे 3 दिसंबर को

राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश में मोदी भी नहीं चाहता कि भाजपा की सत्ता पुनः आए। परंतु तेलंगाना मिजोरम छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मोदी सत्ताहर हाल में एवं की जलसा की ही क्यों ना करनी पड़ेहथियाना चाहता है जो छत्तीसगढ़ मेंजोखनिज संपदा से भरा हुआ छत्तीसगढ़ हथियाना पर वहां की सारी कोल, एल्यूमिनियम लोहा से लेकरसोने तक का खनिजों को हटाने और खदानों को अदानी को सौंपने का संयंत्र करेगा ही करेगा इसलिए जानबूझकर चुनाव की तारीख में और गिनती की तारीख में काफी अंतर रखा गया और आप जानते हैं एवं पूरी चालीसा की है आखिर क्योंभारत में इवीएम से चुनाव करवाए जाते हैं। चक्की सभी कंप्यूटर में अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले देश चीन फ्रांसअमेरिका इंग्लैंडऑस्ट्रेलिया जर्मनी कनाडा आदिअपने यहां ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं करवाते और वह स्वयं स्पष्ट मानते हैंएलएमसीजालसाजी आसानी से संभव है। परंतुमोदी अमित शाहकी अपराधिक जोड़ीदेश के चुनाव आयोग न्यायालयीन व्यवस्था व उन सब शासकीय संस्थाओं को डरा धमका कर अपने बस में कर अपने हिसाब से नचाने के लिए सभी चुनाव इवीएम से करवाने के लिए विवश कर दिया है। जो उसकी सच्चाई बताता हैउसको डराया धमकाया जाता है। घर पर उसके सच सिद्ध करने वाले को पार्टी के और एस एस के गुंडे भेज कर उसको सच सिद्ध करने के लिए किसी भी मंच पर जाने से रोका जाता है।अभी भी इन चुनावों में जो 10 से 12 दिन का अंतर रखा गया है उसके पीछे भी यही कहानी है और सारे राज्यों की स्थिति को समझा जा सकता है।

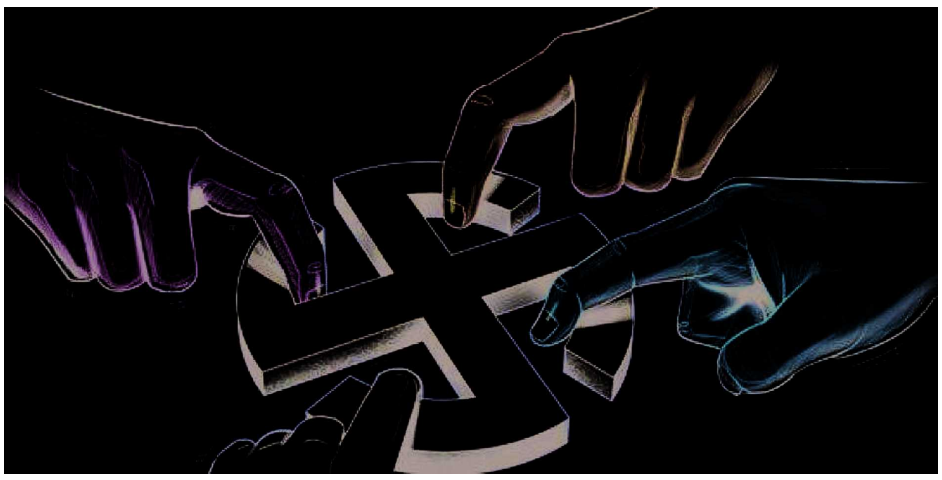

विधानसभा चुनाव 2023

राज्य (कुल सीटें)	चरण	मतदान तिथि	विधानसभा सीटें	मतगणना/चुनाव परिणाम
मध्य प्रदेश (230)	1	17 नवंबर, 2023 (शुक्रवार)	230	3 दिसंबर, 2023 (रविवार)
राजस्थान (200)	1	23 नवंबर, 2023 (गुरुवार)	200	3 दिसंबर, 2023 (रविवार)
तेलंगाना (119)	1	30 नवंबर, 2023 (गुरुवार)	119	3 दिसंबर, 2023 (रविवार)
छत्तीसगढ़ (90)	1	7 नवंबर, 2023 (मंगलवार)	20	3 दिसंबर, 2023 (रविवार)
-	2	17 नवंबर, 2023 (शुक्रवार)	70	3 दिसंबर, 2023 (रविवार)
मिज़ोरम (40)	1	7 नवंबर, 2023 (मंगलवार)	40	3 दिसंबर, 2023 (रविवार)

पांच राज्यों में 7 से 30 नवंबर तक विधानसभा चुनाव होंगे और नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे.16 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. जिनमें 60 लाख युवा पहली बार वोट डालेंगे. इस साल के अंत में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है. पांचों राज्यों में 7 से 30 नवंबर तक विधानसभा चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होंगे. छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को दो चरणों में वोट डाले जाएंगे. राजस्थान में 23 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा.तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी.

राजस्थान में 23 नवंबर को होगा मतदान

राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटों के लिए 23 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती तीन दिसंबर को की जाएगी. चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान में चुनाव की अधिसूचना 30 अक्टूबर को जारी होगी और उम्मीदवार छह नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे. सात नवंबर को नामांकन की जांच होगी और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख नौ नवंबर होगी. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना तीन दिसंबर को की जाएगी. राजस्थान विधानसभा चुनाव के तहत होने वाले मतदान में सवा पांच करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. राजस्थान में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच होता है। इस मरूधर प्रदेश में कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जो चुनिंदा क्षेत्रों में अपना प्रभाव रखती हैं. राज्यप विधानसभा के पिछले चुनाव (2018) में कुल 200 सीटों में कांग्रेस को 99 व भाजपा को 73 सीटें मिलीं. अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव स्थगित कर दिया गया जो 28 जनवरी को हुआ। इसमें भी कांग्रेस ने बाजी मारी। अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. राजस्थान में अभी तक न तो भाजपा ने ही और ना ही कांग्रेस ने किसी उम्मीदवार की घोषणा की है.

मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान

मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए सात नवंबर को मतदान होगा तथा तीन दिसंबर को मतगणना होगी. मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी तथा 20 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. नामांकन पत्रों की छानबीन 21 अक्टूबर को होगी तथा 23 अक्टूबर को नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे. मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को खत्म होगा. इस पूर्वोत्तर राज्य में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है. पिछले विधानसभा चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट ने 26 सीटें जीती थीं तो जोराम पीपुल्स मूवमेंट को आठ और कांग्रेस को पांच सीटें हासिल हुई थीं.

छत्तीसगढ़ में दो चरणों में 7 और 17 नवंबर को मतदान

छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में सात और 17 नवंबर को मतदान संपन्न होगा तथा तीन दिसंबर को मतगणना होगी. नक्सल प्रभावित कुछ क्षेत्रों के चलते संवेदनशील माने जाने वाले छत्तीसगढ़ में पहले चरण में सात नवंबर को 20 सीटों पर मतदान होगा तथा दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 सीटों पर मतदान होगा. राज्य विधानसभा चुनाव के पहले चरण लिए 13 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी तथा 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. पहले चरण में नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को की जाएगी तथा 23 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे. दूसरे चरण के लिए 21 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी तथा 30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की छानबीन होगी तथा दो नवंबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है. भाजपा मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है. राज्य में 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 सीटें जीतकर 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी। भाजपा को 15 सीटें हासिल हुई थीं.

60 लाख युवा पहली बार डालेंगे वोट-EC

अकेले छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव होगा बाकी सभी चार राज्यों में एक ही चरण में वोटिंग होगी.पांच राज्यों में 16 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. जिनमें 8 करोड़ से ज्यादा पुरुष मतदाता और 7.8 करोड़ महिला मतदाता हैं. 60 लाख युवा पहली बार वोट डालेंगे.पाचों चुनावी राज्यों में 679 विधानसभा सीटें हैं. सभी राज्यों में महिलाओं का वोट प्रतिशत पहले से बढ़ा है. वोटर लिस्ट 17 अक्टूबर को जारी की जाएगी, 23 अक्टूबर तक इसमें सुधार किया जा सकेगा.

मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान

मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा और मतों की गिनती तीन दिसंबर को होगी. आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी और नामांकन की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर होगी. नामांकन पत्रों की जांच 31 अक्टूबर को की जाएगी और नाम वापस लेने की अंतिम तारीख दो नवंबर होगी. साल 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 230 सदस्यीय विधानसभा में 114 सीटें जीती थीं और गठबंधन सरकार बनाई थी. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस चुनाव में 109 सीटें जीती थीं. कांग्रेस के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में विधायकों के एक गुट के विद्रोह के चलते कमलनाथ अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और मार्च 2020 में उनके नेतृत्व वाली सरकार गिर गई. सिंधिया गुट के विधायकों के समर्थन से बाद में भाजपा सत्ता में लौटी और शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने. मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने अब तक तीन अलग-अलग सूचियों में 79 उम्मीदवारों की घोषणा की है और अब तक तीन केंद्रीय मंत्रियों सहित कई सांसदों को उम्मीदवार बनाया है जबकि कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों की कोई सूची जारी नहीं की है.

तेलंगाना में सभी 119 विधानसभा सीटों के लिए 30 नवंबर को मतदान

तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 30 नवंबर को मतदान होगा तथा तीन दिसंबर को मतगणना होगी. राज्य विधानसभा चुनाव के लिए तीन नवंबर को अधिसूचना जारी होगी तथा 10 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे. तेलंगाना में नामांकन पत्रों की छानबीन 13 नवंबर को की जाएगी तथा 15 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे. राजीव कुमार ने बताया कि तेलंगाना में सभी 119 विधानसभा सीटों के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा और तीन दिसंबर को मतगणना होगी.

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालय- 0731-2530859, मोबा. 9300755803